

शकुन टाइम्स

जिले में अब तक बीस सीढ़ी धान की खरीद वाराणसी। जिले में अब तक लगभग 20 फीसदी धान की खरीद हो पाई है। तीन दिसंबर तक 826 किसानों से 6596 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। जिले के आठ विकास रोडों में बने 36 केंद्रों पर खरीद चल रही है। पिछले महीने कुछ केंद्रों की खरीद कम होने पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और जिला खरीद अधिकारी विदित श्रीवास्तव ने सभी को फटकार लगाई है। अब इन केंद्रों पर खरीद में तेजी आई है। जिला खाया विपणन अधिकारी सुनील भारती ने बताया कि पिछले वर्ष नवम्बर में 3300 मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद हुई है। वही, इस बार इस अवधि में दोगुना धान खरीदा गया है। ऊर्ध्वों बताया कि सभी केंद्रों पर प्रभारियों को किसानों की सुविधा का ध्यान रखने और लक्ष्य के दिसाब से खरीद के निर्देश दिए गए हैं।

सम्पादकीय

एक नए राजनीतिक नक्षत्र का उमार

हेमंत सोरेन जब दिल्ली आकर अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्यौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को देने आए तो कई लोगों को हैरानी हुई क्योंकि उनकी पिछली पारी में इसी जोड़ी ने उनका राज करना मुश्किल कर दिया था और अखिर में लंबी जेल भी काटने को मजबूर किया था। चुनावी लड़ाई में भी चंपई सोरेन और सीता सोरेन जैसे करीबी लोगों को तोड़कर भाजपा ने अपनी राजनैतिक लड़ाई को काफी हद तक सोरेन परिवार के खिलाफिन्जी खुंदक जैसा बना लिया था। जो लोग हेमंत सोरेन और झारखण्ड के आम आदिवासियों का स्वभाव जानते थे उनके लिए यह न्यौता न तो महज औपचारिकता थी न ही भाजपा के जले पर नामक छिड़कने की कोशिश। न ही इसमें यह जाने का भाव था कि आपने जितना परेशान किया मुझे आदिवासियों और झारखण्डीयों का उतना ही पक्का समर्थन मिला। बताना न होगा कि मोदीजी और शाह की अनुपस्थिति के बिना भी हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड था और उन्होंने चुनावी वायदों को पूरा करने का भरोसा दिया। हेमंत ने इस अवसर पर ही नहीं अपनी सरकार को गिराने की भाजपाई कोशिश के पूरे पांच साल के दौर में बहुत ही मैच्योर पॉलिटीशन होने का प्रमाण दिया, जो उनके पिता शिवु सोरेन अर्थात् गुरुजी समेत कोई आदिवासी नेता नहीं देता था। आप स्वभाव में अन्याय का तगड़ा प्रतिरोध करने वाला आदिवासी अवसर ऐसी स्थितियों में काफी उग्र प्रतिक्रिया देता रहा है जबकि उसके नेता लोभ और दबाव में टूट जाते रहे हैं। यह बात देख भर पर लागू होती है लेकिन झारखण्ड पर खास तौर से। वहां नेता बार-बार शबाइकश हैं लेकिन जनता का बगावती तेवर मद्धिम नहीं पड़ा है। हेमंत ने इसी स्वभाव को पहचान कर उसे अपनी लड़ाई का मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने झारखण्ड और आदिवासियों से भेदभाव का सवाल केन्द्रीय रखा और अपना दावा कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब जेल जाने की स्थिति बनी तो सीधी टकराहट (जैसा दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल ने दिखाया) या अपने परिवार के किसी को कुर्सी सौंपने की जगह कोलहान टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन को गद्दी सौंप दी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गद्दी वापस ली तो भाजपा ने उसे भी मुश्त बनाकर और कुछ लोभ देकर चंपई को अपने पक्ष में किया। माना जाता है कि अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र में आदित्यपुर और गमरिया जैसे जमेशदपुर के शहरी हिस्से न होते तो उनको भी आदिवासी नकार चुके होते।

जबकि हेमंत ने तब भी दो पावर सेंटर न बनाने देने की जबरदस्त व्यावहारिक सोच दिखाते हुए (कहा जाता है कि यह सुझाव सोनिया गांधी का था) मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले ली। और देखा कि उहाँने कितनी मुश्किल लड़ाई को किस आसानी से जीत लिया। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विस्वा सरमा जैसों की महीनों की कवायद और भाजपा का सारा संसाधन धरा रह गया। घुसपैठ का मुद्दा बनाने के लिए भाजपा ने (जिसके असली सूखधार मोदी-शाह ही रहे) आखिरी दिन तक छापा, गिरफ्तारी, कथित मनी-ट्रैल बनाने जैसी सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन कुछ काम न आया। बल्कि उसे अब तक आराम से मिलने वाला ओबीसी वोट भी इस बार पहले से कम हुआ और उसे सिर्फ शहरी और अगढ़ा वोटरों का सहारा रह गया। आदिवासी वोट तोड़ने की सारी कवायद फेल हो गई और अंतिम समय अपनी पार्टी का विलय करके भाजपा अध्यक्ष बने बाबूलाल मारांडी को भूमिहार वोट के सहारे जीताना पड़ा। इसके लिए नाराज पूर्व संसद र्वर्ड राय के मनाना और बागी नित्यांनंद राय को बैठाने में जोर लगाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि भाजपा की तरफ से सिर्फ बाबूलाल मारांडी और चैपई सोरेन ही जीत पाए थे। हेमंत की सफलता दो को छोड़कर सारे आदिवासी ठिकानों से अपने अर्थात झामुमो और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जिताना नहीं है। उसे इससे या अधिकांश आदिवासी वोट पाने भर से ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। सारी रिजर्व सीटों पर तो भाजपा पिछली बार भी हारी थी। हेमंत का असली बड़ा काम है अलग-अलग कबीलों में अब तक बंटे हो जारखंड के आदिवासी समाज को एकजुट करना। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिक्षा सोरेन उरांव प्रभुत्व के तमाड़ इलाके में जाकर अनजान पीटर से हार गए थे। आदिवासियों की नई एकजुटता तो भाजपा द्वारा पहला गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री (रघुवर दास) बनाना से ही शुरू हुई थी लेकिन उसे एक अंजाम तक लाना आसान न था। हेमंत ने यह काम किया और आज वे शिक्षा सोरेन समेत किसी भी आदिवासी नेता की तुलना में बड़ा और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी जबाबदेही ज्यादा बड़ी है-जारखंड के साथ मुल्क भर के आदिवासियों की आवाज बनाना और देश की राजनीति में आदिवासी स्वर को अधिक प्रमुख स्थान दिलाना। हेमंत ने अपना कौशल इंडिया गठबंधन के साथी दलों के दावों और उम्मीदवारों को संभालने में भी दिखाया। यह जरूर है कि राहुल गांधी ने उनको प्री-हैंड दिया लेकिन झारखंड चुनाव अभियान लगभग पूरी तरह हेमंत के कंधों से ही चला। अगर कोई श्रेय में दावेदारी कर सकता है तो वह उनकी पती कल्पना सोरेन ही हैं जिन्होंने घटक दलों की पंचायत या सरकारी कामकाज भी निपटाने जैसे जिम्मों से मुक्त होकर हेमंत से भी ज्यादा चुनावी सभाएं कीं।

लालुरु का १००० वर्षों का जबकि यहाँ के लोगों को दावा था कि राम सातपुते को सौ, दो सौ वोटों से अधिक नहीं मिल सकते, इसमें ईंटीएम की गड़बड़ है। अपने संदेह को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि हम अपने खर्च और व्यवस्था से मतपत्रों से पिछ से चुनाव कराएंगे, इसके लिए उन्होंने मालशिरस के तहसीलदार को अनुमति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन अनुमति देने की जगह प्रशासन ने यहाँ न केवल बोट डालने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, बल्कि धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी ताकि एक साथ पांच लोग इकट्ठा न हो पाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू करने का ऐलान किया गया है।

जनकली भारतीय मुद्रा की बढ़ती संख्या से अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने का दबाव

ਨੂੰ ਬਨਯਾ

अहंगभार चिंता का विषय है कि महात्मा गांधी (नई) प्रधानमंत्री ने अपने दो संसदीय वर्षों के लिए 2018-19 और 2023-24 के बीच लगभग चार गुना, और 2020-21 से 2,000 रुपये के नकली नोटों की तीन गुना हो गयी है। यान रहे कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं और नेहरू रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मई 2023 में 2000 के मुद्रा नोटों को वापस लेने के कदम के बाद से इनमें से 98 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। लेकिन 00 और 200 रुपये के नकली नोटों का तेजी से बढ़ता चलन चिंता का विषय बन गया है। 500 रुपये के नोट उजर्मा के लेन-देन की रीढ़ बन गये हैं और पिछले कुछ दिनों में इसके प्रचलन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अमरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस बात से चिंतित हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने देश में नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन को लेकर लोकसभा में चिंता जताई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में 2,18,650 लाख पीस नकली नोट पकड़े गये थे। 2022-23 में यह 9,11,100 लाख के उच्चतम स्तर पर हुंच गया, जो 2023-24 में थोड़ा कम होकर 8,57,110 लाख हो गया। यह 2018-19 में पकड़े गये 2,18,650 लाख पीस से काफ़ी अधिक है। हालांकि, पकड़े नहीं गये नकली नोटों की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।

अर्ध-शारी बाजारों में प्रचलन में होते हैं। संचालक और ग्राहक पहचान से बचने के लिए बैंकों से बचते हैं। नकली भारतीय मुद्रा नोटों का उपयोग मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को पंग बनाने और आर्थिक आतंक पैदा करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल और असम की सीमाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से नकली भारतीय मुद्रा के प्रमुख प्रवेश बिंदु हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही देश के पूर्वी हिस्से में नकली भारतीय मुद्रा भेजने के लिए नेपाल का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में, पुलिस द्वारा नकली मुद्रा संचालन पर एक बड़ी कार्रवाई में, असम के गोलायाट शहर के गुलाम पट्टी क्षेत्र से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

नलों के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा गुजरात, हरियाणा, तरंग प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में टेके पर जदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है। कहा जाता है कि उनमें से कई बांगलादेश के जरिये तप्तकरी काके लाये थे नकली भारतीय नोटों के कूरियर के तौर पर इस्तेमाल करके जाते हैं। हाल ही में, बांगलादेश में नकली भारतीय नोटों की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क कापी बढ़ गया है। हाल ही में इमा के जरिये भारत में जाली भारतीय मुद्रा के अवैध प्रेरण (पीपीएम) माप का उपयोग किया जाता है। नकली मुद्रा वैश्विक समस्या उत्पन्न करती हैं। यू.एस. डॉलर को दुनिया के सबसे ज्यादा जाली मुद्रा कहा जाता है। कुछ नकली यू.एस. डॉलर बहुत उच्च गुणवत्ता के बताये जाते हैं। धोखेबाज उन वैध मुद्रा के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं, या उनका उपयोग ऋण या क्रेडिट लाइन प्राप्त करने के लिए करते हैं। 2002 में मुद्रा लॉन्च होने के बाद से दूसरा सबसे लोकप्रिय नकली बैंक नोट यूरो है। हालांकि, दुनिया के कई हिस्सों पर



हल है ढाका में पुलिस न बड़ा सच्चा में जाला भारतीय मुद्रा नोटों से भरी बोरियां जबत की थीं। ढाका में स्थानीय मीडिया बांग्लादेश पुलिस के हवालों से कहा कि पाकिस्तान में आहोर स्थित एक सिंडिकेट ऐसे जाली नोट छापता है, जिन्हें अब संग्रहमरक के पथरों से भरे कठनरों में श्रीलंका के जरिये बांग्लादेश ले जाया जाता है। भारत में तस्करी से पहले सिंडिकेट के सदस्यों के घरों में विशेष कक्षों में खेप छिपाई गयी है। बांग्लादेश में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के उछाल का ताता भारतीय पुलिस ने एक जांच के बाद लगाया था। यह गया गया कि उन अवैध मुद्रा नोटों को पाकिस्तान में छापा या था और पिछे उन्हें नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के द्वारा दुर्भाग्य से अवैध रूप से भारत में आयात किया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश जाली भारतीय मुद्रा नोटों के दो प्रमुख उत्पादक और वितरक हैं। इसका लक्ष्य आतंकवाद को फंड देना, भारत में मुद्रास्पीति दर बढ़ाना और द्वारा में विश्वास को कम करना है। अंतरराष्ट्रीय आपाराधिक लिस्स संगठन (इंटरपोल) के अनुसार, जालसाजी वित्तीय धनों से भूमिगत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और अंगठित आपाराधिक तथा आतंकवादी नेटवर्क की तिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जाली मुद्रा की मात्रा का ही आकलन करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन

मुत का बड़ा कामत

फिलहाल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आर्थिक संकट चुनावी अभियानों के दौरान किए गए लोकलुभावन वायदों के चलते ही उत्पन्न हुआ है। जिसके कारण प्रिष्ठले दिनों हिमाचल में कर्मचारियों को बेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने में व्यवधान देखा गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं को तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था। सत्ता में आने पर राज्य सरकार ने अपने वायदे को अमली जापा पहनाया। जिसके चलते चालू वित्त वर्ष के लिये बीस हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी बिल आया है। इसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिये पुरानी पेंशन लागू करने का वायदा किया। यह तय था कि इस घोषणा से राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस आसन्न संकट को महसूस करते ही विंगत में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से हाथ खींच लिया था। लेकिन अब हिमाचल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को पुनर्जीवित करने से, पहले से ही संकटग्रस्त सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ और बढ़ गया है। वहीं पंजाब में सब्सिडी भुगतान में देरी से पंजाब की स्थिति और खराब हो गई है। संग्रह दक्षता में भारी गिरावट आई है। दरअसल, पीएसपीसीएल पहले ही ट्रांसमिशन घाटे में वृद्धि के संकट से जूझ रहा है। हालांकि, पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली के बिल के बकायादारों और कतिपय सरकारी विभागों से बकाया धनराशि वसूलने से राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

जिसकी कीमत कालांतर राज्य की आर्थिकी को ही चुकानी होगी। निश्चित तौर पर पंजाब को मुफ्त की बिजली देने से उत्पन्न संकट से जल्दी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। राज्य फिलहाल उधार हासिल करने की सीमा के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते मुफ्त बिजली योजना चलती रह सकेगी, इसमें सदैह है। कमोबेश हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही संकट से दो चार है। राज्य की वित्तीय बदहाली इस बात की गवाह है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली ने राज्य के वित्तीय दायित्वों को बढ़ा दिया है। जिसके चलते बेतन और पेंशन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये मासिक रूप से दो हजार करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। जो वित्तीय दिक्षितों की अंतहीन शृंखला को जन्म दे रही है। राज्य 6200 करोड़ आर्थिक मामलों के जानकार चिंता जता रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र का राजस्व घाटा अनुदान आधा होने की बात कही जा रही है। वहीं अपने लोकलुभावनी नीतियों के दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करके दोनों राज्यों की सरकारें ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर फंड रोकने और भेदभावपूर्ण रखवा अपनाने का आरोप ही लगाया है। वहीं दूसरी ओर पूँजी निवेश योजना के लिये विशेष सहायता से हिमाचल को बाहर किए जाने पर तल्ख राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ ऐसे ही पंजाब सरकार भी विकास निधि के आवंटन में पक्षपात का आरोप केंद्र सरकार पर लगातार रही है। जबकि यह एक हकीकत है कि चुनावी लोकलुभावनवाद से प्रेरित अस्थिर राजकोपीय नीतियां ही संकट के मूल में हैं। यह टकसाली सत्य में कि राज्य सरकारें बढ़ाते कर्ज और घटते राजस्व के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। यह बक्त की दरकार है कि राज्य सरकारें अपना ध्यान खेराब बांटने के बजाय संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित करें। दरअसल, राज्यों की वित्तीय संकट से उबरने के लिये राजकोपीय विवेक, कुशल कर संग्रह और तार्किक सब्सिडी समय की मांग है।

संग्रह दक्षता में भारी गिरावट आई है। दरअसल, पीएसपीसीएल पहले ही ट्रांसमिशन घोटे में बृद्धि के संकट से जूझ रहा है। हालांकि, पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली के बिल के बकायादारों और कतिपय सरकारी विभागों से बकाया धनराशि वसूलने से राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

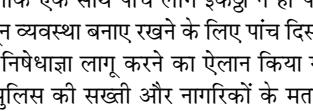
जिसकी कीमत कालांतर राज्य की आर्थिकी को ही चुकानी होगी। निश्चित तौर पर पंजाब को मुफ्त की बिजली देने से उत्पन्न संकट से जल्दी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। राज्य फिलहाल उधार हासिल करने की सीमा के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते मुफ्त बिजली योजना चलती रह सकेगी, इसमें सदैह है। कमोबेश हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही संकट से दो चार है। राज्य की वित्तीय बदहाली इस बात की गवाह है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली ने राज्य के वित्तीय दायित्वों को बढ़ा दिया है। जिसके चलते वेतन और पेंशन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये मासिक रूप से दो हजार करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। जो वित्तीय दिक्कतों की अंतहीन शृंखला को जन्म दे रही है। राज्य 6200 करोड़ आर्थिक मामलों के जानकार चिंता जता रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र का राजस्व घाटा अनुदान आधा होने की बात कही जा रही है। वहीं अपने लोकलुभावनी नीतियों के दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करके दोनों राज्यों की सरकारें ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर फंड रोकने और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप ही लगाया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब निवेश योजना के लिये विशेष सहायता से हिमाचल को बाहर किए जाने पर तल्ख राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ ऐसे ही पंजाब सरकार भी विकास निधि के आवंटन में पक्षपात का आरोप केंद्र सरकार पर लगातार रही है। जबकि यह एक हकीकत है कि चुनावी लोकलुभावनवाद से प्रेरित अस्थिर राजकोषीय नीतियां ही संकट के मूल में हैं। यह टकसाली सत्य में कि राज्य सरकारें बढ़ाते कर्ज और घटते राजस्व के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। यह वक्त की दरकार है कि राज्य सरकारें अपना ध्यान खैरात बांटने के बजाय संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित करें। दरअसल, राज्यों का वित्तीय संकट से उबारने के लिये राजकोषीय विवेक, कुशल कर संग्रह और तार्किक सब्सिडी समय की मांग है।

डालने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी अटल है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की रक्षा बल्कि धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लाग कर मालशिरस के एक गांव में अगर फिर से

पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस उत्साहित महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों में बड़ी गढ़बड़ी की आशंकाओं और सवालों के बीच 3 दिसम्बर को चुनाव आयोग के सामने एक सुनहरा मौका आया था कि वह अपनी साख को सुधार ले। यह मौका दिया था कि मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने। लेकिन चुनाव आयोग ने यह अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। दरअसल मालशिरस विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम जानकर को जीत हासिल हुई है, उन्होंने भाजपा के राम सातपुरे को 13,147 वोटों से हराया है, लेकिन मरकरवाड़ी गांव में राम सातपुरे को उत्तम

जानकर से अधिक वोट मिले।
श्री जानकर को 843 और श्री सातपुते को 1003 वोट मिले, जबकि यहां के लोगों को दावा था कि राम सातपुते को सौ, दो सौ वोटों से अधिक नहीं मिल सकते, इसमें ईवीएम की गडबड़ है। अपने संदेह को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि हम अपने खर्च और व्यवस्था से मतपत्रों से पिछ से चुनाव कराएंगे, इसके लिए उन्होंने मालशिरस के तहसीलदार को अनुमति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन अनुमति देने की जगह प्रशासन ने यहां न केवल

दी ताकि एक साथ पांच लोग इकट्ठा न हो पाएं।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच दिसंबर
तक निषेधाज्ञा लागू करने का ऐलान किया गया
है। पुलिस की सख्ती और नागरिकों के मतदान



मिले थे, तो इस बार उत्तम जानकर को कम और राम सातपुते को ज्यादा बोट कैसे मिल सकते हैं। ग्रामीणों की यह आशंका मतपत्रों से चुनाव से दूर हो सकती थी और तब भी नतीजे आर 23 तारीख को आए नतीजों की तरह रहते, तो ऐसे में चुनाव आयोग का दावा पुख्ता हो जाता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की गई। छोटी सी आवादी वाले एक गांव में मतपत्रों से चुनाव की एक छोटी सी कवायद पर अनावश्यक सख्ती दिखाकर चुनाव आयोग और भाजपा दोनों ने अपने चारों तरफबन चुके संदेह के धेरों को और गाढ़ा कर लिया है। इधर महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार बनाने में देरी हो रही है, उससे भी कई सवाल उपज रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान हो गया था, 23 तारीख को नतीजे आ गए और नतीजों में भाजपानीत महागठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है, इसके बावजूद अब तक सरकार गठन का काम लटका हुआ है। निवृत्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कभी हाँ, कभी ना और भाजपा की दबाव बनाकर सत्ता को मुश्ति में रखने की राजनीति ने महाराष्ट्र की जनता के भविष्य को अधर में लटका दिया है। 70 सालों में शायद ही ऐसा मौका किसी राज्य में आया होगा कि किसी दल या गठबंधन को प्रचंड बहुमत उपर लग जाए। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो चुका है और अगर किसी की भी तरफ से सरकार बनाने का प्रस्ताव न जाए तो कायदे से राज्यपाल को स्वतंत्र कार्रवाई कर लेनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में कायदा भी शायद दिल्ली से और दिल्ली का ही चत रहा है, इसलिए महायुति की बैठक के लिए तारीख पर तारीख घोषित हो रही है और इन पंक्तियों के लिखे जाने तक न कोई बैठक हुई, न कोई फैसला हुआ। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 23 तारीख से दिल्ली और मुंबई के बीच महायुति वेनेताओं के आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया। यह तय हो गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अजित पवार उपमुख्यमंत्री पद के लिए पिसे मान गए हैं, लेकिन भाजपा ने यह स्पष्ट ही नह किया कि उसकी तरफ से देवेंद्र फड़नवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आएगा या किसी अन्य को इस बार महाराष्ट्र की गद्दी सौंपी जाएगी। एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तो राज हो गए, लेकिन इसके बदले उहें क्या चाहिए, इस पर भी मामला अटका रहा। श्री शिंदे का सरकार गठन की चर्चा से दूर दो दिन तक अपने गांव जाकर बैठना और बार-बार बीमार पड़ना भी इस बात की तरफ इशारा करता है।

